BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXV | 15th October 2014 | No. 15

चैम्बर की बैठक में नगर विकास मंत्री बोले :
राजधानी में लगेंगे 97 सीसीटीवी कैमरे व ट्रैफिक लाइट, बनेगा मेगा कंट्रोल रूम

ट्रैफिक की जानकारी अब एलइडी स्क्रीन पर

बैठक को संबोधित करते नगर विकास मंत्री श्री सम्राट चौधरी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के अग्रवाल, भागलपुर के मेयर श्री दीपक भुवानियाँ, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, नगर विकास उप-समिति के चेयरमैन श्री नन्हे कुमार तथा दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं अन्य।

नगर विकास विभाग शहर के बदहाल ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक नयी पहल शुरू कर रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों में 97 सीसीटीवी और ट्रैफिक सिगनल लगाने के साथ ही 25 प्रमुख चौक-चौराहों पर एलइडी डिस्पले लगाये जायेंगे, जिन पर ट्रैफिक की पूरी जानकारी दी जायेगी। किस रोड में कितने समय तक जाम रहेगा और किस रास्ते में नो ट्रैफिक है, इसकी जानकारी के साथ तापमान भी बताया जाता रहेगा। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 25 एलइडी टीवी से लैस एक मेगा ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाया जायेगा, जिसकी निगरानी नगर विकास विभाग, पटना पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम करेगी। यह टीम ट्रैफिक समस्याओं की लगातार मॉनीटरिंग करेगी। कैमरे पर ट्रैफिक की स्थिति देख कर जहां पुलिस जरूरतवाले क्षेत्र में एक्टिव रहेगी वहीं ट्रैफिक कानूनों को धत्ता बतानेवालों से परिवहन विभाग फाइन वसूलेगा। इधर अपराधियों की करतूतों को भी पुलिस लगातार वॉच करने के साथ कानून व्यवस्था के हालात बिगाड़नेवालों पर भी नजर बनी रहेगी। दिनांक 13 अक्टूबर 2014 को नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके लिए जल्द ही सभी विभागों की बैठक कर अविलंब कार्रवाई शुरू की जायेगी। हम यह भी विचार कर रहे हैं कि इस कंट्रोल रूम के जरिये हम लोगों को कचरा उठाव की जानकारी दें और उनसे यह भी सूचना प्राप्त करें कि उनके इलाके में कचरा उठाया गया है या नहीं?

मास्टर प्लान पर एसएमएस से मांगी जायेगी प्रतिक्रिया : नगर विकास मंत्री ने कहा कि सरकार पटना का एक बेहतर मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। इसे और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों के सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। इस कड़ी में हम सेमिनार आयोजित कर सीधे लोगों से बात कर उनकी राय नोट करेंगे और पूरे पटना के लोगों को एसएमएस से सूचना देकर वेबसाइट पर उनकी सलाह भी आमंत्रित करेंगे। होल्डिंग टैक्स भी 2014-15 का लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक सभी 72 वार्डों को फॉगिंग मशीन उपलब्ध करा दी जायेगी।

व्यापारियों ने दिये शहर को संवारने के सुझाव : बैठक में व्यापारियों ने नगर विकास मंत्री को शहर को संवारने के उपाय सुझाये। बिहार चैबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों के कई सुझाव हैं, ताकि अपना शहर भी सुंदर बन सकें।

• राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कूड़े फेंकने के निश्चित स्थानों को चिह्नित किया जाये और वहां कचरा डालने की समुचित व्यवस्था की जाये। • उन जगहों पर कचरा डालने का समय, उठाने का समय का बोर्ड लगाया जाये। बाद में कचरा फेंकने पर दंड का भी प्रावधान हो। • वहां सीसीटीवी भी लगाया जाये और सभी जिम्मेवार अधिकारियों के नंबर प्रदर्शित किये जाये। • क्षेत्रों के गण्यमान्य लोगों द्वारा सफाई व्यवस्था का निश्चित अवधि पर सर्टिफिकेशन भी कराया जाये। • निगम के प्रत्येक वार्ड में पांच स्थानीय लोगों की कमेटी बनायी जाये, जो सफाई की मॉनीटरिंग करे। • गार्बेज और वेस्टेज से खाद का प्रोजेक्ट बनाया जाये। • आवारा पशुओं के लिए बने कांजी हाउस। • अपार्टमेंट निर्माण सामग्री से दूसरे को परेशानी नहीं हो, तो रात में निर्माण रोका जाये। • ऑटो व टैक्सीचालकों को नाम की पट्टी के साथ वर्दी भी दिया जाये।

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ

ब्लैकलिस्टेड हुई गैमन इंडिया लिमिटेड : नगर विकास विभाग ने गैमन इंडिया लिमिटेड कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। साथ ही सरकार ने कंपनी द्वारा पटना वाटर प्रोजेक्ट के लिए दिये गये एडवांस के 65 करोड़ रुपये को भी जब्त कर लिया है।

नगर विकास मंत्री ने बताया कि सरकार अब किसी भी कंपनी को बरदाश्त करने के मूड में नहीं है। पटना वाटर प्रोजेक्ट में हो रही लेटलतीफी के मद्देनजर हमने यह फैसला लिया है। पहले यह सोचा था कि 31 दिसंबर तक कंपनी को समय दिया जाये, लेकिन कार्यशैली में सुधार नहीं होने पर यह कार्रवाई की गयी। आगे भी इस तरह की कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा, इस कारण सभी कंपनियां तय समय में गुणवत्ता के साथ काम खत्म करने पर सारा ध्यान फोकस करें। मंत्री ने शहर में नागरिक सुविधाओं के मद्देनजर कई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार सभी नालों से अतिक्रमण हटवायेगी। छठ के बाद यह कार्रवाई शुरू की जायेगी, हमने इसके लिए कोर्ट को लिखित तौर पर जानकारी भी दे दी है। सरकार 350 सीवरेज भी बना रही है। श्री चौधरी ने कहा कि शहर में खुले में मांस नहीं बेचा जायेगा। सरकार वधशाला का निर्माण शुरू करने जा रही है, जमीन एलॉट कर दिया गया है। निर्माण के लिए केंद्र भी 10 करोड़ रुपये देगा। वधशाला के निर्माण से सालाना एक करोड़ टैक्स भी प्राप्त होगा। **(साभार : प्रभात खबर, 14.10.2014)**

बिहार चैम्बर की ओर से माननीय नगर विकास मंत्री को समर्पित ज्ञापन (13.10.2114)

1. राजधानी का Drainage System काफी पुराना हो गया है। पटना के बहुत सारे पुराने/नये इलाके विशेष कर पटना सिटी के क्षेत्र एवं पटना के श्रीकृष्ण नगर, किदवईपुरी, राजेन्द्र नगर तथा कंकड़बाग जैसे पुरानी कॉलोनियों में इस समस्या के निराकरण के उपाय प्राथमिकता के आधार पर किये जाने चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नया Drainage System को अनिवार्य रूप से एक निश्चित समय सीमा के अन्दर स्थापित करने की सख्त आवश्यकता है । Proper Linkage of Drains अथवा Alternate Drain System स्थापित कर इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है । कुछ नये बने नालों में बिना ईंट, गिट्टी हटाये उसे ढक दिया गया है, फलस्वरूप पानी का निकास नहीं हो पाता है जैसे- पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, अल्पना मार्केट, बोरिंग रोड, बेउर जेल, सिपारा को जोड़ने वाली मुख्य जल निकासी पूरी तरह से ब्लॉक है। पटना के विभिन्न क्षेत्रों में नालों की सफाई का सघन अभियान निगम द्वारा यथाशीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

2. कूड़े-कचरे के ढेर के कारण कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पटना राजधानी है। यद्यपि निगम द्वारा कूड़ा उठाने एवं सफाई का काम किया जाता है परन्तु इसकी व्यवस्था पूर्णत: अपर्याप्त है। अत: पटना को साफ एवं स्वच्छ रखने के संबंध में हमारा निम्न सुझाव है :-

(i) राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कूड़े फेकने की निश्चित स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए तथा वहाँ पर कचरा डालने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(ii) उक्त स्थलों पर कचरा डालने का समय, इसे उठाने का समय आदि से संबंधित बोर्ड लगाकर आमलोगों को सूचित किया जाना चाहिए और यदि निर्धारित समय के बाद कचरा डाला जाता है तो दण्ड के प्रावधान तय कर उसे भी उक्त बोर्ड पर प्रचारित किया जाना चाहिए। इसे सख्ती से लागू करने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा सकता है। प्रथम फेज में सीसीटीवी कैमरा वैसे इलाके में लगाया जाए जहाँ के निवासी सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बिजली तथा उपयुक्त स्थान उपलब्ध करा सकें। साथ ही सफाई से संबंधित पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं उनका मोबाइल नम्बर भी बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए।

(iii) संबंधित क्षेत्रों के सम्मानित नागरिकों द्वारा सफाई व्यवस्था की निश्चित समय अवधि पर Certification कराया जाए।

(iv) पटना नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूर्णरूपेण चुस्त-दुरूस्त करने हेतु हमारा सुझाव है कि प्रत्येक वार्ड में स्थानीय निवासियों में से 5 आदमियों की एक कमिटी बनायी जाए, जो निगम की साफ-सफाई का Monitoring कर सकें तथा समय-समय पर वरीय अधिकारियों को भी वस्तुस्थिति से अवगत करा सकें।

(v) पटना शहर के सभी सड़कों की सफाई मशीन द्वारा करायी जानी चाहिए।

3. पटना नगर निगम को Garbages and Wastes से बायों फर्टिलाइजर्स तैयार करने के प्रोजेक्ट पर विचार करना चाहिए। ऐसी परियोजना Public Private Partnership के आधार पर स्थापित एवं कार्यशील की जा सकती है।

4. शहर के क्षेत्रों एवं सड़कों से आवारा पशुओं, सुअरों एवं कुत्तों इत्यादि को दूर रखने की नितांत आवश्यकता है। ऐसे जानवर लोगों को अत्यधिक कष्ट पहुँचाते हैं, गंदगी बढ़ाते हैं एवं महामारी के कारक होते हैं ।

5. शहर की अधिकांश सड़कों पर विचरण करने वाले जानवरों एवं पशुओं पर लगाम कसने या उन्हें पकड़कर कॉजी हाउस में बन्द करने जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे कि इन जानवरों की वजह से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके ।

6. पटना में बहुमंजली भवन के विकास की काफी संभावना है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि निर्माण नियमानुसार किया जाए। बहुमंजली भवन बनने वाले क्षेत्रों में Drainage System, Water line तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए। बहुमंजली भवन बनने वाले स्थलों के निवासियों एवं आने-जाने वालों को कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए निर्माण सामग्रियों को समुचित तरह से रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही Noisy Pollution या अधिक आवाज से होने वाले परेशानियों पर अंकुश लगाने के लिए रात के समय में निर्माण कार्य को जहाँ तक संभव हो Discourage करना चाहिए। भवन निर्माताओं को भी आवश्यक नागरिक सुविधाएं यथा– पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्ष लगाना, सही तरीके से Drainage System एवं Water Line की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ गन्दे पानी एवं मल के निकास का समुचित प्रबंध करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जा सकता है।

7. शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर सुव्यवस्थित ऑटो-रिक्शा एवं टैक्सी स्टैण्ड की स्थापना होनी चाहिए। टैक्सी/ऑटो रिक्सा चालकों के लिए नाम की पट्टी के साथ वर्दी अनिवार्य किया जाना चाहिए। पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर नि:शुल्क एवं सशुल्क पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. **पटना के मास्टर प्लान के संबंध में**

(i) प्रस्तावित मास्टर प्लान में बरसात के पानी को इकट्ठा करने हेतु किसी भी बड़े Water Bodies को चिन्हित नहीं किया गया है। पटना मास्टर प्लान में जल संसाधनों को और मजबूती प्रदान करने हेतु बड़े-बड़े Water Bodies को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(ii) वर्त्तमान पटना के उत्तरी किनारा (गंगा के उत्तर) पर कोई विकास नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रस्तावित मास्टर प्लान में इस क्षेत्र की पटना के साथ मजबूत Connectivity को दर्शाया गया है, जो विकास के लिए बहुत ही अहम है। अत: प्रस्तावित मास्टर प्लान में गंगा के उत्तरी इलाकों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(iii) प्रस्तावित मास्टर प्लान में सड़क के साथ बिजली वितरण को नहीं दर्शाया गया है।

(iv) प्रस्तावित मास्टर प्लान में सड़क के साथ सीवरेज, दूरसंचार एवं गैस आपूर्ति व्यवस्था को नहीं दर्शाया गया है।

(v) प्रस्तावित मास्टर प्लान में पुनपुन को नये प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए चिन्हित किया गया है जो Flood Zone Area में आता है अत: प्रस्तावित एयरपोर्ट को बाढ़ से सुरक्षा के साधनों पर विचार किया जाना चाहिए।

(vi) प्रस्तावित मास्टर प्लान में भूमि अधिग्रहण के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है।

(vii) प्रस्तावित मास्टर प्लान को तैयार करने हेतु 2001 के Data के स्थान पर 2011 जनगणना की Data का उपयोग होना चाहिए।

(viii) प्रस्तावित मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र सिर्फ 2% है, जो कि लगभग 10% होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए 25% चिन्हित की गई है। पटना

को एक बड़े शहर के रूप में विकसित करने की मंशा हेतु कृषि क्षेत्र को 25% के औचित्य पर विचार किया जाना चाहिए।

(ix) प्रस्तावित मास्टर प्लान में पटना शहर में Green Space को चिन्हित नहीं किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र एवं आवासीय क्षेत्र के बीच Green Buffer Zone को चिन्हित किया जाना चाहिए।

(x) जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ पटना में वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे शहर में वाहन प्रदूषण में इजाफा होगा। वाहन प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु Environment Friendly ईंधन जैसे CNG के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए, परन्तु प्रस्तावित मास्टर प्लान में CNG Outlet की कोई व्यवस्था नहीं दर्शाया गया है।

(xi) मोनो रेल/मेट्रो रेल को प्रस्तावित मास्टर प्लान में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि पटना की संकीर्ण सड़कों और भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए यह भी एक विकल्प हो सकता है।

(xii) प्रस्तावित मास्टर प्लान में Central Spine- 80m wide Road, Pocket outer Road- 60m wide एवं Pocket Major Road (45m wide) प्रस्तावित है, पर साईकिल एवं रिक्शा के लिए अलग ट्रैक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसका प्रावधान होना चाहिए, जिससे यातायात समस्या न उत्पन्न हो।

(xiii) प्रस्तावित मास्टर प्लान में बहुत सी चीजें जो वर्त्तमान में Exist है, सरकार द्वारा मास्टर प्लान में नहीं दर्शाया गया है।
(a) गंगा किनारे प्रस्तावित सड़क (मैरिन ड्राइव) (b) पटना-गया भाया गौरीचक सड़क (c) बिहटा-सरमेरा सड़क।

(xiv) प्रस्तावित मास्टर प्लान में सभी गंगा घाटों को विकसित एवं सौंदर्यीकृत किया जाना चाहिए। दाह-संस्कार के लिए चिह्नित घाटों पर समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्मानित

श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष को माला पहनाकर सम्मानित करते चैम्बर के महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा। साथ में चैम्बर के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में चल रहे इंफ्रास्ट्रकचरल डेवलपमेंट कार्यों में चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा पूरी तत्परता, समुचित देख-रेख द्वारा कार्यों का सम्पादन एवं पूरा समय देने के लिए दिनांक 14.10.2014 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में श्री मुकेश कुमार जैन की प्रशंसा एवं सराहना की गई। कार्यकारिणी सदस्यों ने श्री जैन का माल्यार्पण कर उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया।

विश्व दृष्टि-दिवस की पूर्व संध्या पर चैम्बर में नि:शुल्क नेत्र जाँच एवं जारूकता कार्यक्रम

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 8 अक्टूबर 2014 को विश्व दृष्टि दिवस की पूर्व संध्या पर नि:शुल्क नेत्र जाँच एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष विश्व दृष्टि दिवस का थीम है 'ठीक होने वाली दृष्टिहीनता अब और नहीं।'

चैम्बर अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि दिनांक 9 अक्टूबर 2014 को विश्व दृष्टि दिवस है। इस दिवस के एक दिन पूर्व ही चैम्बर में नि:शुल्क नेत्र जाँच एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर चैम्बर ने विश्व दृष्टि दिवस में अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है। इस आयोजन से लोगों में होने वाली दृष्टि दोष के बारे में जागरूकता होगी।

इस कार्यक्रम में विलास नेत्रालय के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि

विश्व-दृष्टि दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सुबोध कुमार जैन एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शशि मोहनका।

मोहनका और उनकी टीम ने आँखों की जाँच की। जाँच के साथ दवाईयाँ भी दी गई। डॉ. शशि मोहनका ने बताया कि पूरी दुनिया में लगभग 285 मिलियन लोग कम दृष्टि और अंधेपन के शिकार हैं। इनमें 39 लाख लोग नेत्रहीन हैं और 246 लाख लोग कम या गंभीर दृष्टि दोष के शिकार है। इनमें 5 में से 4 लोगों का दृष्टि दोष रोका जा सकने वाला है। डॉ. मोहनका ने बताया कि 90 प्रतिशत दृष्टिहीन कम आय वाले देशों में रहते हैं। एक अनुमान के आधार पर 19 लाख बच्चे दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। दुनिया के पूरे नेत्रहीनों में 65 फीसदी नेत्रहीन 50 वर्ष या उसके अधिक उम्र के लोग हैं जबकि इस आयु वर्ग के लोग पूरी आबादी का 20 प्रतिशत है।

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक डॉ. गीता जैन ने इस अवसर पर कहा कि विश्व में हर पाँच सेकेण्ड में एक व्यक्ति को दृष्टि दोष हो जाता है जबकि 89 फीसदी बच्चों में दृष्टि दोष पाँच वर्ष की आयु से पहले हो जाता है।

इस अवसर पर चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जैन, श्री सुबोध जैन, श्री एम. पी. जैन भी उपस्थित थे। जागरूकता कार्यक्रम में 100 लोगों के आँखों की जाँच हुई।

हाजीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की प्रदेश सरकार से मांग

व्यवसायी आयोग का गठन होना जरूरी

हाजीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष शशि मोहन, हाजीपुर चैम्बर के अध्यक्ष श्री निशांत गांधी एवं अन्य

हाजीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में राज्य में व्यवसायियों के हितों की हिफाजत के लिए व्यवसायी आयोग के गठन की मांग की गयी। सम्मेलन रविवार दिनांक 21.9.2014 की शाम हाजीपुर के बूबना स्मृति भवन में हुई जिसकी अध्यक्षता हाजीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निशांत गांधी ने की।

इस अवसर पर बिहार चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि हाजीपुर को ग्रेटर पटना के मास्टर प्लान में शमिल किया जाना जरूरी है क्योंकि हाजीपुर पटना का उपनगर जैसा है। सम्मेलन में महिलाओं की अच्छी उपस्थिति की सराहना करते हुए उन्होंने चैम्बर के पदधारकों को महिलाओं को अधिक संख्या में सदस्य बनाने का निर्देश दिया। अपने पूर्व वक्ता के इस कथन पर कि सरकार को आनेवाले वर्षों में कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि कृषि महत्वपूर्ण और बड़ा सेक्टर है लेकिन उसमें कुछ वैल्यू एडीशन करने पड़ेंगे तभी वह ज्यादा कारगर साबित होगी।

प्रारंभ में निशांत गांधी ने कई प्रस्ताव पेश किए जिनमें व्यवसायी आयोग के साथ-साथ सभी उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों, मेडिकल आदि में व्यवसायियों के बच्चे-बच्चियों के लिए कोटा निर्धारित करने, हाजीपुर नगर के मध्य में पुलिस चौकी की स्थापना, सभी सरकारी कमेटियों में चैम्बर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, नगर से जलनिकासी की कारगर व्यवस्था करने और नगर व जिले की सभी विकास योजनाओं के निर्माण से लेकर उनके कार्यान्वयन की पूरी प्रकिया में चैबर का परामर्श अनिवार्य बनाने की मांगें शामिल थीं। इन प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित किया गया।

इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष शशि मोहन, महामंत्री ए. के. पी. सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य विशाल टेकरीवाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हाजीपुर चैम्बर के सचिव तारकेश्वर प्रसाद, संयुक्त सचिव संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष दिनेश सिंह, मीडिया प्रभारी द्वारिका सिंह, रवि चौधरी, विवेक कुमार आदि ने अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। अनेक व्यवसायियों को इस अवसर पर चैम्बर की ओर से उनके योगदान के लिए प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ।

(साभार : हिन्दुस्तान, 22.9.2014)

सर्किल दर से जुड़ीं शिकायतों के बाद बिहार सरकार ने लिया इसकी समीक्षा का निर्णय

बिहार में जमीन की बढ़ती कीमत को देखते हुए राज्य सरकार अब सर्किल दरों की समीक्षा करने जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने बिहार में जमीन की कीमत युक्तिसंगत बनाने का भी फैसला लिया है। इस बारे में राज्य सरकार इस महीने के अंत तक आखिरी फैसला ले सकती है।

अहम फैसला : • राज्य सरकार जमीन की सरकारी कीमत के निर्धारण पर देगी खासा ध्यान, राज्य में जमीन की सरकारी कीमत बाजार भाव के करीब रखने पर विचार • उद्यमी और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी काफी दिनों से सर्किल दर में रियायत की कर रहे हैं मांग। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.10.2014)**

उद्योगों के लिए डेवलप जमीन का 10% भाग किसानों को होगा वापस

राज्य सरकार उद्योगों के लिए डेवलप जमीन का दस प्रतिशत भाग किसानों को भुफ्त में वापस कर देगी। यानी पूरी कीमत भुगतान करने के बावजूद सरकार उद्योगों के लिए जमीन का नब्बे प्रतिशत भाग ही इस्तेमाल करेगी। शेष दस प्रतिशत भूभाग का इस्तेमाल जमीन मालिक फिर से अपनी इच्छा के अनुसार कर सकेंगे। शर्त यह होगी कि सरकार जमीन की कीमत सर्किल रेट के अनुसार देगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 19.9.2014)

उद्योगों के लिए उदार होंगे पर्यावरण नियम

केंन्द्र सरकार वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्कों के आसपास उद्योगों के लिए पर्यावरण नियमों में और ढील देने की पहल करने जा रही है। राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की सीमा हटाए जाने के राज्यों के प्रस्ताव पर भी पर्यावरण मंत्रालय विचार करने जा रहा है। साथ ही केंद्र की ओर से यह भी संभव किया जाएगा कि उसकी मंजूरी के बिना ही परियोजना पर शुरुआती काम जल्दी अंजाम दिया जाना संभव हो सके।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.10.2014)

मुनाफा वाले उद्योगों में होगा निवेश

राज्य सरकार बिहार के अच्छे बिजनेस मॉडल वाले उद्योगों में निवेश करेगी। वह अच्छे और लाभकारी उद्योगों का शेयर खरीदेगी। सरकार ने इसके लिए फंड मैनेजर की तलाश शुरू कर दी है। फंड मैनेजर के रूप में जिसकी भी नियुक्ति होगी वह शेयर बाजार का बड़ा नाम होगा। ऐसे अब तक टाटा कैपिटल और रिलायंस कैपिटल ने सरकार की इस योजना में रूचि दिखाई है।

राज्य सरकार की लाभकारी उद्योगों का शेयर खरीदने की योजना वर्ष 2011 में ही बनी थी। लेकिन तब वित्त विभाग ने इसपर असहमति जता दी । लिहाजा योजना खटाई में पड़ गई। अब इसे नए सिरे से लागू करने पर काम चल है। सरकार की इस योजना से राज्य के उद्योगों को पूंजी की परेशानी नहीं रहेगी। साथ ही सरकार को भी लाभांश मिलेगा। उद्योग विभाग योजना को जमीन पर उतारने के लिए लगभग सौ करोड़ का कैपिटल वेंचर फंड बनाने का विचार कर रहा है। इससे अधिक पैसे की जरूरत होने पर फंड मैनेजर के रूप में तय की गई कंपनी व्यवस्था करेगी। उन कंपनियों को भी लाभांश का हिस्सा मिलेगा।

राज्य में कई ऐसे उद्योग हैं, जो लाभकारी तो हैं लेकिन पैसे की कभी के कारण कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। छोटे और मझोले उद्योगों की परेशानी भी कुछ इसी तरह की है। पूंजी के अभाव में सेकड़ों इकाइयां बीमार पड़ी हुई हैं। बैंकों का रवैया भी उद्योगपतियों के प्रति सहयोगात्मक नहीं है। लोन देने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उद्योगपति बैंकों का चक्कर लगाकर थक जाते हैं। इन सारी परेशनियों को दूर करने में सरकार की यह योजना सहायक साबित होगी।

निवेश के अनुसार राज्य में उद्योग

500 करोड़ से अधिक – 47	10 से 100 करोड़ – 255
100 से 500 करोड़ – 107	10 करोड़ से नीचे – 606

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.10.2014)

लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए शाखाएं खोलेगा स्टेट बैंक

देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) देश भर में प्रतिबद्ध शाखाएं खोलकर लघु एवं मध्यम उपक्रम क्षेत्रों में ऋण का दायरा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक के पास अतिरिक्त नकदी है क्योंकि बड़ी कंपनियां निवेश रोक रही हैं। एसबीआई की अध्यक्ष अरूंधती भट्टाचार्य ने कहा, 'इससे पहले हमारे पास लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एसएमई) के लिए टीम और शाखाएं थी और कर्ज का आवंटन एसएमई ऋण प्रकोष्ठ के मूल्यांकन के बाद किया जाता था जो फैक्ट्री की अवधारणा है। लेकिन हमने पाया है कि ऐसे कारोबारी मॉडल में स्वामित्व का अभाव होता है इसलिए हम प्रतिबद्ध लघु एवं मध्यम उपक्रम शाखाएं खोल रहे हैं जो सिर्फ एसएमई क्षेत्र को ऋण देगा।' पिछले लगभग तीन साल अर्थव्यवस्था में नरमी के बीच बड़ी कंपनियां विशेष तौर पर बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियां बड़ी संख्या में चूक कर रही हैं। हालांकि एसएमई क्षेत्र से चूक बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिला है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 6.10.2014)

बड़े उद्यमियों की संभावना नगण्य

खुलेंगे 3,500 और वसुधा केन्द्र, निश्चित समय पर होगी इनमें बैंकिंग

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में बड़े उद्यमियों के आने की संभावना नगण्य है। ऐसे में छोटे उद्यमियों पर फोकस करने की आवश्यकता है। सूबे से छोटे-छोटे उत्पादों के निर्माण की संभावना अन्य राज्यों से अधिक है। वे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की 'बिजनेस कॉरस्पांडेंट' के बिहार मॉडल पर आधारित रिपोर्ट जारी करते हुए बोले रहे थे। सिडबी के लिए यह रिपोर्ट माइक्रोसेव प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है, जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। केवल इसके कुछ बिन्दुओं से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया।

"सिडबी के साथ मिलकर डीएफआईडी बिहार, उत्तरप्रदेश, ओडिशा और मध्यप्रदेश में 30 मिलियन पाउंड की राशि से निर्धनतम राज्य समावेशी वृद्धि (पीएसआइजी) नामक वित्तीय समावेश कार्यक्रम चला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कम आय वाले 12 मिलियन परिवारों की पहुंच वित्तीय सेवाओं तक बढ़ाना है।"

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 19.9.2014)

महिला उद्यमियों पर भी ध्यान

बिहार में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार अब उनके लिए एक खास योजना बना रही है। इसके तहत इन उद्यमियों को राज्य सरकार ब्याज दरों में रियायतें देने के बारे में सोच रही है। साथ ही, राज्य सरकार अपनी औद्योगिक नीति के तहत भी इनके लिए सुविधाओं में इजाफा कर सकती है।

• लघु एवं मझोले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार महिला उद्यमियों को देगी हरसंभव सुविधाएं • सरकार इन उद्यमियों के लिए बाजार का भी करेगी इंतजाम • उत्पाद बेचने में भी राज्य सरकार महिला उद्यमियों की करेगी मदद • इनकी मदद के लिए जरूरत पड़ने पर नियमों में होगा फेर-बदल • प्रशिक्षण और सरकारी प्रोत्साहन में भी इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 19.9.2014)**

एमएसएमई पोर्टल पर सूबे के उद्यमी हैं काफी पीछे

बिहार में एमएसएमई की हालत चिंताजनक है। उद्यमियों का कहना है कि एमएसएमई सेग्मेंट में रजिस्ट्रेशन के लिए 4-6 महीने विभाग के चक्कर काटने के बाद ही काम हो पा रहा है।

केंद्रीय मंत्री कालराज मिश्रा ने पिछले दिनों ई-कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल को लांच किया था। इसके जरिए कोई भी एमएसएमई अपने खुदरा उत्पाद एवं उपकरण सीधे बेच सकते हैं।

तकनीकी रूप से बीटूसी अर्थात बिजनेस टू कस्टमर के लिए www.msmeshopping.com पर पंजीयन की व्यवस्था की गई है, परंतु अब तक बिहार से मात्र 3 सप्लायर ही रजिस्टर्ड हुए हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रूपए सालाना है। इसमें उत्पादों की खरीद-बिकी की कोई सीमा नहीं है। हर ट्रांजेक्शन (लेन-देन) पर कोई शुल्क भी नहीं देना है। इसके बावजूद पटना और बिहार से रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरप्रेन्योर सामने नहीं आ रहे। उद्योग विभाग से जुड़े अधिकारी नाम नहीं छापने के अनुरोध के साथ बताते है कि अब तक इस संदर्भ में जागरूकता के लिए विभाग का प्रयास शून्य ही है। कुटीर स्तर पर काम कर रहे बिहार के उद्यमी तकनीकी रूप से अपडेटेड नहीं हैं।

• 45 प्रतिशत सहभागिता है एमएसएमई की देश के कुल औद्योगिक विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) में • 08 प्रतिशत योगदान है जीडीपी में एमएसएमई का • 40 प्रतिशत योगदान है देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का • 358 उत्पाद शामिल हैं एमएसएमई की आरक्षित कैटोगरी में।

"बिहार में बैंकों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। बैंकों का रवैया एमएसएमई के प्रति नकारात्मक है। एनपीए के बहाने छोटे-छोटे ऋण को रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ई-कॉमर्स से जुड़ने पर उद्यमियों के पास पर्याप्त मात्रा में सामान हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। पूंजी के बिना यह संभव नहीं है।"

– प्रदीप कुमार, डायरेक्टर, एमएसएमई

(साभार : दैनिक भास्कर, 7.10.2014)

CORPORATES ARE NOT FACING TAXING TIMES

Businesses and society have a symbiotic relationship : A stable and progressive society will benefit companies

Most of the affected companies have accepted, mostly unwillingly, the requirement under the Companies Act of 2013, that a company must spend at least 2% of its average profit before tax, in the preceding three years on corporate social responsibility (CSR) projects if it falls within the purview of Clause 35 of the Act. However, they want tax incentives for effectively complying with CSR obligations while the government is reportedly planning to introduce a penalty clause for those repeatedly not meeting the target. At present there is no penalty and the ministry can only question firms that do not provide adequate explanation for non-compliance.

(Details : H. T. , 8.10.2014)

फ्यूल सरचार्ज वसूली का फैसला टला

• उपभोक्ताओं को राहत, कंपनी नहीं दे पाई लेखा-जोखा • बिजली पर 29 पैसे प्रति यूनिट वसूलने की तैयारी।

फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 29 पैसे प्रति यूनिट वसूली का मामला टल गया। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष यू. एन. पंजियार ने विद्युत कंपनी द्वारा 12 माह में बिजली खरीद का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं करने पर फैसला नहीं सुना सके।

विद्युत कंपनी के अभियंताओं को कहा कि पहले लेखा-जोखा प्रस्तुत करें। तब आयोग इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। विद्युत कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपभोक्ताओं द्वारा उपभेग की गई बिजली पर प्रति युनिट 29 पैसे की दर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली की अनुमति मांगी है। विद्युत कंपनी का कहना है कि टैरिफ निर्धारण के समय निर्धारित राशि से अधिक की बिजली खरीदी गई। जिसकी भरपाई के लिए सरचार्ज वसूली जरूरी है। दो सितंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई थी। जनसुनवाई में आयोग के सदस्य यूसी झा, आइए खान भी मौजूद थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 19.9.2014)

बिजली बिल के साथ दो भाग में देना होगा सिक्योरिटी चार्ज

नया कनेक्शन देने के लिए पेसू ने तैयार किया नया सॉफ्टवेयर

शिविर के दौरान नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन देने वाले उपभोक्ताओं के लिए पेसू ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। इससे बिजली बिल के साथ दो भागों में सिक्योरिटी भेजा जाएगा। जो बिल के साथ सिक्योरिटी चार्ज नहीं जमा करेंगे, उनका कनेक्शन तीसरे महीने काट दिया जाएगा। पेसू जीएम राजीव अमित के अनुसार, 12 सितंबर से 22 सितंबर तक बीच लगे शिविर में 8600 लोगों ने नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया है। इनमें 3200 लोगों को कनेक्शन दे दिया गया है।

लोड बढ़ाने का चार्ज : घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिकिलो वाट 400 रूपए सिक्योरिटी चार्ज देना होगा। लोड बढ़ाने से बिल पर इसका असर नहीं पडेगा। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट 1200 रुपए सिक्योरिटी चार्ज देना होगा। इन्हें 50 यूनिट बिजली बिल प्रतिकिलो वाट के हिसाब से प्रतिमाह न्यूनमत जमा करना ही होगा।

नया कनेक्शन लेने का चार्ज : घरेलू उपभोक्ताओं को दो किलोवाट का नया कनेक्शन लेने के लिए 1275 रुपए देने होंगे। इसमें 800 रुपए सिक्योरिटी चार्ज, 400 रुपए लेबर चार्ज एवं 75 रुपए आवेदन शुल्क लिये जाएंगे। व्यावसायिक उपभोक्ताओं से दो किलोवाट का नया कनेक्शन लेने पर 2875 रुपए देने होंगे। इनमें 2400 रुपए सिक्योरिटी जार्च, 400 रुपए लेबर चार्ज, 75 रुपए कनेवशन चार्ज लिए जाएंगे।

लगेगा सर्विस वायर : • 07 किलोवाट तक सिंगल फेज का कनेक्शन होता है • 01 से 4 किलोवाट के बीच लगेगा 5 एमएम का तार •5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन में लगेगा 6 से 10 एमएम का तार • 2.85 रुपए प्रति यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल • 4.75 रुपए प्रति यूनिट-कमार्शियल उपभोक्ताओं का बिजली बिल।

(साभार: दैनिक भास्कर, 8.10.2014)

बिजली का लोड अब बढ़ा सकते हैं 31 दिसंबर तक

मुफ्त कनेक्शन के लिए 10 से लगेगा फिर विशेष शिविर

राजधानी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। खासकर जो अब तक बिना कनेक्शन के घर व दुकान में बिजली जला रहे हैं। इन्हें एक और मौका मिलने जा रहा है बिना पैसे जमा किए नए कनेक्शन लेने का।

बिजली कंपनी की ओर से शहर में 10 से 20 अक्टूबर तक नए कनेक्शन के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा। वहीं वैसे उपभोक्ता जिनके घर या दुकान में स्वीकृत लोड से अधिक बिजली की खपत है, वे घर या दुकान का लोड बढ़ा सकते हैं। दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 31 दिसंबर 2014 तक स्वैच्छिक लोड वृद्धि योजना को बढ़ा दिया है। पेसू के बिलिंग काउंटरों व कस्टमर केयर सेंटरों से लोग आवेदन लेकर लोड बढ़वा सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक पटना में 12 से 22 सितंबर तक लगे शिविर में 27 मेगावाट बिजली का लोड बढ़ाया गया था। इससे कंपनी के खाते में हर माह लाखों रुपए जमा होंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.10.2014)

सीबीआई में शामिल हों आयकर अधिकारी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में जांच को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए आयकर, कस्टम और लेखा परीक्षण से जुड़े अधिकारियों को जांच एजेंसी का हिस्सा बनाने का सुझाव केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने दिया है। सवीसी के सुझाव पर सीबीआई गौर कर रही है। आयोग के अनुसार इससे जांच एजेंसी के कामकाज में तेजी आएगी और जांच ज्यादा प्रभावी तरीके से होगी।

सूत्रों का कहना है कि सीवीसी कई मामलों में जांच की देरी से चिंतित है। पिछले दिनों हुई बैठकों में जांच में देरी का मसला सीवीसी ने उठाया है। उसका मानना है कि सीबीआई में अगर आयकर, कस्टम या लेखा परीक्षण में जांच का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लाया जाता है, तो सीबीआई की जांच की विशेषज्ञता बढ़ेगी। कई मामले ऐसे होते हैं जहां कई तरह के तकनीकी सहयोग की जरूरत होती है। आयोग का मानना है कि कई मामलों में जांच की देरी की वजह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का उद्देश्य ही खतरे में पड़ जाता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.9.2014)

बिहार ने केंद्र सरकार से मांगी और बिजली

बिहार ने केंद्र से बिजली का कोटा बढ़ाने की मांग की है। राज्य की बिजली परियोजनाओं में कम से कम आधा और नेपाल व भूटान की बिजली परियोजनाओं से भी बिजली मांगी है। बीते दिनों ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार ने मांग रखी।

संकट दूर हो : • नेपाल और भूटान की परियोजनाओं से भी मांगी बिजली • बिजली संकट का हवाला दे राज्य ने केंद्र से किया अनुरोध • कहलगांव के स्टेज दो से 750 मेगावाट बिजली की मांग।

क्या है स्थिति : देश की कुल आबादी का 9 प्रतिशत हिस्सा बिहार में रहता है। लेकिन, यहां एक व्यक्ति साल में 144 यूनिट बिजली खपत करता है, जो देश में सबसे कम है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली खपत 917.20 यूनिट है।

यह है आधार : केंद्र से बिहार को 1948 मेगावाट आवंटित है पर औसतन 1300 मेगावाट बिजली हर दिन मिलती है। केंद्रीय नीति के तहत कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत बिजली राज्यों को जरूरत के अनुसार देना है। जिस राज्य में बिजली घर लगे, उसको होम शेयर के रूप में 10 फीसदी व अनावंटित कोटे के तहत 15% बिजली प्राथमिकता के आधार पर मिलनी है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 28.9.2014)**

जिस बैंक में खाता, वहां एटीएम शुल्क नहीं!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को इस बात की आजादी दी है कि एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) के जरिये एक माह में पांच बार से ज्यादा लेनदेन करने वाले अपने ग्राहकों से वह शुल्क वसूल सकते हैं। नई व्यवस्था इस साल नवंबर से शुरू होगी। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने ग्राहकों के हित में कदम उठाते हुए इस पर अमल नहीं करने की योजना बनाई है।

खुद के बैंक में मिल सकती है राहत : • आरबीआई ने नवंबर से बैंकों को एटीएम शुल्क वसूलने की दी आजादी • हालांकि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों से एटीएम शुल्क लेने के पक्ष में नहीं। **(बिज़नेस स्टैंडर्ड, 19.9.2014)**

भारतीय मध्यम वर्ग की कमाई अमेरिका से दो दोगुनी बढ़ी

भारतीय मध्यम वर्ग की कमाई अमेरिका के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। वर्ष 1988 से 2008 के बीच आकलन के मुताबिक भारतीय मध्यम वर्ग की आमदनी में 50 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के मध्य वर्ग की आय 26 फीसदी की दर से बढ़ी है। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने ताजा रिजोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2015-16 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4 फीसदी की तेज गति से बढ़ सकती है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.10.2014)

विदेशों से पैसा भेजने में सबसे आगे हिन्दुस्तानी

विदेशों से पैसा कमा कर देश भेजने के मामले में भारत पहले अव्वल स्थान पर रह सकता है। दुनिया भर में फैले भारतीय इस साल तकरीबन 71 अरब डॉलर भारत भेज सकते हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 70 अरब डॉलर रहा था। इस लिहाज से देश मिलने वाली विदेशी मुद्रा में 1.5 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात की कही गई है। खास बात यह है कि 2013 में भारत में आए 22 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) की तुलना में यह रकम तीन गुनी ज्यादा है।

विदेशों से धन : • भारत 71 अरब डॉलर • चीन 64 अरब डॉलर • फिलिपींस 28 अरब डॉलर • मैक्सिको 24 अरब डॉलर • पाकिस्तान 17 अरब डॉलर • बांग्लादेश 15 अरब डॉलर • वियतनाम 11अरब डॉलर।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.10.2014)

तत्काल से मिलेगा रेलव को माल

वित्त वर्ष 2014 में यात्री परिचालन से नुकसान 26, 000 करोड़ रुपये के पार जाने की वजह से भारतीय रेलवे कुछ खास मार्गों पर विशेष मूल्य निर्धारण मॉडल के तहत 50 फीसदी तत्काल टिकटों की बिक्री कर कुछ अतिरिक्त कमाई करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यदि यह नया प्रयोग सफल साबित हुआ तो इससे रेलवे को 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.10.2014)**

बंद हो तत्काल कोटे से वेटिंग टिकट

तत्काल कोटे से केवल कंफर्म बर्थ मिले, रेलयात्रियों की यह मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। बिहार दैनिक यात्री संघ का कहना है अगर रेलवे अब कंफर्म बर्थ देने में सक्षम नहीं है, तो तत्काल चार्ज न ले या फिर इस कोटे से केवल कंफर्म बर्थ सुनिश्चित करें शुरुआती दिनों में कंफर्म बर्थ की गारंटी देने जैसी सेवा के नाम पर यात्रियों से तत्काल चार्ज वसूले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। एक ओर रेलवे वेटिंग टिकट पर सफर न करने की हिदायत देता है, दूसरी तरफ लाखों तत्काल टिकट बेचकर भी यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं देता। जानकारी के अनुसार पिछले सात सालों में रेलवे ने तत्काल स्कीम से करोड़ों का मुनाफा कमाया है।

तत्काल टिकट बिक्री

वित्तीय वर्ष	आय	वित्तीय वर्ष	आय
2007-08	374	2011-12	847
2008-09	605	2012-13	994
2009-10	672	2013-14	1298
2010-11	729		

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.9.2014)

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

दिनांक - 01.04.2014 की तिथि से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दर निम्न प्रकार से निर्धारित है :-

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दि० 01.04.2012 + 01.10.12 + 01.04.13 + 01.10.2013 से लागू परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी होगी	01.04.2014 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	144.00+7.00+6.00+ 11.00+8.00=176.00	8.00	184.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	150.00+8.00+6.00 +11.00+9.00=184.00	8.00	192.00 प्रतिदिन
3	कुशल	183.00+9.00+8.00 +14.00+11.00=225.00	9.00	234.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	223.00+11.00+9.00 +17.00+13.00=273.00	12.00	285.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	4134.00+207.00+ 174.00+316.00+242.00 =5073.00	219.00	5292.00 प्रतिमाह

गंगा को मैला करने वाले उद्योगों पर शिकंजा शुरू

केंद्र सरकार ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने गंगा में गंदगी में बहाने वाली 764 औद्योगिक इकाइयों की शीर्ष स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें उन उपायों पर चर्चा की जाएगी जिसके जरिये गंगा की निर्मल बनाया जा सके। माना जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए नए मानदंड जारी कर सकती है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 8.10.2014)

बड़े शहरों में होगा बिहार फाउंडेशन चैप्टर

राज्य के औद्योगिक वातावरण में सुधार एवं पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित बिहार फाउंडेशन देश के इस वित्तीय वर्ष में अन्य शहरों में अपने चैप्टर खोलेगा। अभी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों व कई देशों में इसके चैप्टर हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार फाउंडेशन को 3.10 करोड़ रुपये सहायक अनुदान की मंजूरी दी है। **(साभार : दैनिक जागरण, 8.10.2014)**

BIMARU STATES NO LONGER BIMARU

EXTRACTS FROM ASSOCHAM REPORT JUNE 2014

(A) The study of ASSOCHAM dated June 2014 reveals that the traditional BIMARU States have started moving up the scale and has considerably reduced the gap between the progressive states and this has occurred not only in terms of PCI (Per-Capita) income but also in terms of these States substantially improving its own revenue collections and balancing the same with Central grants and its Share in Central taxes.
The following table 1 & 2 shows the growth of PCI of BIMARU states and of the Higher Income states.

TABLE 1 Convergence of Slates trend growth rale
Per Capita Income (PCI) Trend Growth Rate

STATES	Annual Trend Growth rate 1980-1993	Annual Trend Growth rate 1993-2004	Annual Trend Growth rate 2004-2013
HIGH INCOME STATES			
Gujarat	2.9	2.9	8.2
Haryana	3.5	3.7	6.9
Kerala	2.6	4.1	6.0
Maharashta	4.1	2.8	7.2
Punjab	3.1	2.2	4.8
LOWER INCOME STATES			
Assam	1.1	0.9	4.6
Bihar	**1.1**	**1.7**	**7.2**
Madhya Pradesh	1.9	1.7	6.5
Odisha	1.6	2.3	4.5
Rajasthan	3.5	2.8	6.3
Uttar Pradesh	2.2	1.1	5.4

The figures for Bihar, one on the BIMARU States has achieved a growth from 1. 1% 1.7 % to 7.2% shows the determination of the State to catch up with the higher income states. This has occurred due to its investments in rural roads, irrigation, agriculture, education and public health. There has been a substantial increase in agricultural production and improvement in availability of power.

A study of the states Nominal GDP show that the BIMARU states are not very far bebind that of the advanced states. The table below shows that Bihar has grown faster than any other state and has a growth rate higher than some of the advanced states of Maharashtra & Gujarat.

TABLE 2 States Nominal GDP between FY 2006 and FY 2012 along with Median value of the seven year data. (All figures in percentage)

STATES	FY 2006	FY 2012	Median Value *
Whole of india	9.48	6.88	8.37
HIGH INCOME STATES			
Maharashtra	15.13	11.13	10.78
Andhra Pradesh	14.95	6.87	10.10
Tamil Nadu	13.96	12.39	11.74
Gujarat	9.57	13.79	12.02
Kerala	10.09	7.80	8.77
Haryana	9.20	8.12	9.20
Punjab	5.90	5.79	6.61
LOWER INCOME STATES			
Assam	3.40	8.42	5.72
Bihar	**0.92**	**13.13**	**13.13**
Odisha	5.18	7.18	7.75
Rajasthan	6.68	10.97	7.88
UP	6.51	6.23	6.95
MP	5.31	11.58	9.23
TWO TRIBAL STATES			
Meghalaya	10.52	13.62	13.39
Mizoram	11.00	14.67	15.75

**Median value estimate by ASSOCHAM*

(B) Most of the BIMARU states have improved their fiscal conditions on their own and Bihar is a living example how the state has been turned around which is illustrated by following tables 3 & 4. The state of Bihar has garnered a growth rate of 283.9% in States Own Non-Tax Revenue which is way above of even the High Income states.

TABLE 3 High Income States *(Values in Rs. Crore)*

	2011-12 (Accounts)	2013-14 (Budget Estimates)	Growth Rate
GUJARAT			
States Own Tax Revenue	44252.3	60207.8	36.1
Share in Central Taxes	7780.3	8199.9	5.4
States Own Non-Tax Revenue	5278.5	6379.5	20.9
Grants from the Centre	5849.8	9044.8	54.6
HARYANA			
States Own Tax Revenue	20399.5	28784.3	41.1
Share in Central Taxes	2681.6	3083.9	15.0
States Own Non-Tax Revenue	4721.7	5162.5	9.3
Grants from the Centre	2754.9	6349.6	130.5
KERALA			
States Own Tax Revenue	25718.5	46914.9	82.4
Share in Central Taxes	5990.4	8143.8	35.9
States Own Non-Tax Revenue	2592.2	4821.6	86.0
Grants from the Centre	3709.2	6221.4	67.7
MAHARASHTRA			
States Own Tax Revenue	87608.5	107259.6	22.4
Share in Central Taxes	13343.3	18111.7	35.7
States Own Non-Tax Revenue	8167.7	11993.6	46.8
Grants from the Centre	12168.8	18621.9	53.0

TABLE 4 Low Income States *(Values in Rs. Crore)*

	2011-12 (Accounts)	2013-14 (Budget Estimates)	Growth Rate
ASSAM			
States Own Tax Revenue	7638.2	8983.8	17.6
Share in Central Taxes	9283.5	12620.7	35.9
States Own Non-Tax Revenue	2866.7	3400.3	18.6
Grants from the Centre	7666.9	16279.5	112.3
BIHAR			
States Own Tax Revenue	12612.1	20962.7	66.2
Share in Central Taxes	27935.2	37981.0	36.0
States Own Non-Tax Revenue	889.8	3416.1	283.9
Grants from the Centre	9883.0	17706.7	79.2
ODISHA			
States Own Tax Revenue	13442.7	17605.0	31.0
Share in Central Taxes	12229.1	15903.9	30.0
States Own Non-Tax Revenue	6443.0	6825.0	5.9
Grants from the Centre	8152.2	10965.1	34.5
RAJASTHAN			
States Own Tax Revenue	25377.1	34053.1	34.2
Share in Central Taxes	14977.0	20380.9	36.1
States Own Non-Tax Revenue	9175.1	12654.4	37.9
Grants from the Centre	7481.5	10152.1	35.7

PT. GPO/R-10/NP-15/2014-2016 R.N. 4211/62

चैम्बर में नये सदस्यों का स्वागत

मेसर्स द्वापर ट्रेडर्स के प्रोपराइटर श्री गोपाल कृष्णा को सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारीगण ।

मेसर्स डॉयनोड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी (प्रा0) लिमिटेट के निदेशक को सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारीगण ।

दिनांक 26 जुलाई, 2014 को कार्यकारिणी समिति की बैठक में जिन सदस्यों की सदस्यता स्वीकृत हुई थी, उनका दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान कर स्वागत किया। 26 जुलाई, 2014 को जिनकी सदस्यता स्वीकृत हुई थी, वे हैं:- (1) मेसर्स द्वापर ट्रेडर्स, गोविन्द मित्रा रोड, पटना- 800004 (2) मेसर्स डॉयनोड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी (प्रा०) लिमिटेट, न्यू डाक बंग्ला रोड, पटना- 800001 एवं (3) मेसर्स सान्या फार्मा, लालजी टोला, पटना- 800001 । मेसर्स सान्या फार्मा के प्रतिनिधि अपरिहार्य कारणवश इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये।

मेसर्स ग्रीन प्लाई इण्डस्ट्रीज लि0 के कामर्शियल मैनेजर श्री विनय गोयनका को सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारीगण ।

मेसर्स जया न्यूट्रीसन्स प्रा0 लि0 के निदेशक श्री नीतीन अभिषेक को सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारीगण ।

दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को कार्यकारिणी समिति की बैठक में जिन सदस्यों की सदस्यता स्वीकृत हुई थी, उनका दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान कर स्वागत किया। 18 सितम्बर, 2014 को जिनकी सदस्यता स्वीकृत हुई थी, वे हैं:- (1) नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुजफ्फरपुर (2) मेसर्स ग्रीन प्लाई इण्डस्ट्रीज लि0,पटना एवं (3) मेसर्स जया न्यूट्रीसन्स प्रा० लि०, पटना सिटी- 800001 । नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि अपरिहार्य कारणवश इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये।

ईपीएफओ सदस्य जान पाएंगे खाते का हाल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब पांच करोड़ सदस्य मध्य अक्टूबर से अपने खातों की ताजा स्थिति की जानकारी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।

अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ उपभोक्ता एक वेब पोर्टल के जरिए अपने परमानेंट या सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) को देख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को यह पोर्टल लांच कर सकते हैं। कंपनियों के लिए ईपीएफओ में अपने कर्मचारियों के बैंक एकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है। यूएएन से उपभोक्ता अपना खाता देख सकते हैं और पेंशन योग्य सेवा भी देख सकते हैं। यूएएन पोर्टेबल होगी यानी कर्मचारी नौकरी बदलने पर और देश में किसी भी जगह नौकरी करने पर भी समान यूएएन का उपयोग कर सकेंगे। इसलिए संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के दावे को हस्तांतरित करवाने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.10.2014)

अंतत : वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मिल गई जमीन

• 24.95 एकड़ भुमि पर लगेगा प्लांट • दीघा में लगाया जाना है विशाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

आखिरकार राज्य सरकार को गांगा के पानी को शुद्ध करने के लिए लगाए जाने वाले प्लांट के लिए जमीन मिल ही गई। जमीन मिलने के साथ ही इस बात की संभावना बढ़ गई है कि शहर की बड़ी आबादी को एक निश्चित मियाद के बाद घर बैठे ही गंगा जल पीने को मिल सकेगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.10.2014)**

नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगा गंगा ड्राइव-वे का काम

दीघा से दीदारगंज के बीच गंगा ड्राइव-वे का अटका हुआ काम अगले महीने के पहले हफ्ते से फिर आरंभ हो सकता है। पथ विकास निगम के अनुसार गंगा ड्राइव-वे निर्माण के लिए नहीं की धारा का अध्ययन आई आई.टी. रुड़की से कराया गया था। उसने रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नदी की धारा कहां और किस तरह से इस प्रोजेक्ट को भ्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट मे यह भी बताया गया है किस माह में नदीं की धार किस तरह होगी। **(हिन्दुस्तान, 7.10.2014)**

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296